

2 February, 2022

The rural employment lifeline further weakened by derisively low budget allocation

Notwithstanding the rural distress, implementing NREGA is a legal obligation of the Central government. However, the demand-driven nature of the Act has been repeatedly stifled in letter and spirit. By severe rationing of funds, it has been made a supply driven programme. Today is NREGA diwas and while we are supposed to be celebrating the idea of rural employment guarantee, we are deeply pained that the programme is systematically undermined by ridiculously low budget allocation.

The total allocation outlay for the ministry of rural development has [decreased by 12%](#) in the Union Budget 2022-23, adding on to the existing distress of the rural economy. While for MGNREGA, despite revised estimates for the current financial year coming in at around Rs 98,000 crore, the budgetary allocation has stayed the same as last year, at Rs 73,000 crore. Out of this, about [Rs.18,350 crore](#) are pending liabilities from previous years. Therefore, only about Rs 54,650 cr is available for next year.

If the government wants to provide legal guarantee of work to all the active job card holding households, which is [9.94cr](#), then considering the current budgetary estimate, it will only be able to provide some 16 days at [per person per day average cost of Rs 334](#)¹.

Since 2015-16, the annual budget allocation has never been sufficient to provide work to all those seeking employment under the program. In fact, every year about 80-90% of the budget gets exhausted within the first 6 months, resulting in heavy slowdown of work on the ground. The government has not been able to provide employment to all active job card holding families due to inadequate budget allocation.

It is well known that NREGA has served as a lifeline for millions of distressed households in the last couple of years and helped rural India cope with the unprecedented unemployment caused by the unilaterally imposed national lockdown in FY 2020-21. It has almost worked as a vaccine for unemployment in rural India which is still struggling to recover from enormous loss of lives and livelihoods. While in FY 2020-21 the central government ended up spending Rs.1.11 lakh crore for a record 11 crore workers from 7.5 crores households who worked under NREGA, in FY 2021-22, a 34% reduction in budget allocation caused much lesser employment generation on ground. The government later on added a supplementary budget of Rs. 25000 crore in view of the growing need for work across rural India. As of now 9.75 cr workers from 6.74 cr households have worked in NREGA this financial year despite frequent interruptions in implementation due to great delays in fund release from the centre.

¹ cost per person calculated at 12% hike from the current year.

We have recommended in our pre-budget note that no less than Rs.3.62 lakh crore will be needed to ensure maximum employment generation for all active job card holding families.

The Government has once again failed millions of its rural citizens who depend on the rural employment guarantee programme for meeting their life needs.

We, members of NREGA Sangharsh Morcha express our deep disappointment at this ridiculously low budget allocation for NREGA and **we urge that the central government should take necessary actions within a month to allocate adequate funds for the programme.**

We also expect quick action to strengthen social audits across the nation and to ensure that independent social audits are regularized in all states, findings are put in public domain and timely actions are ensured against each irregularity.

For further information, please write at nrega.sangharsh.morcha@gmail.com or contact :

Debmalya: 7294184845 | Anuradha: 9433002064 | Chakradhar: 9246522344 |

Tapojay: 7718011678 | Mukesh: 9468862200 on behalf of NREGA Sangharsh Morcha.

2 February, 2022

उपहासपूर्ण रूप से कम बजट आवंटन से ग्रामीण रोजगार जीवन रेखा और कमजोर हुई

ग्रामीण संकट के बावजूद, नरेगा को लागू करना केंद्र सरकार का कानूनी दायित्व है। हालांकि, अधिनियम की मांग-संचालित प्रकृति को बार-बार दबा दिया गया है। धन की गंभीर नियंत्रित वितरण करके, इसे आपूर्ति संचालित कार्यक्रम बना दिया गया है। आज नरेगा दिवस है और माना जाता है कि हम ग्रामीण रोजगार गारंटी के विचार का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का गहरा दुख है कि इस कार्यक्रम को उपहासपूर्ण रूप से कम बजट आवंटन द्वारा व्यवस्थित रूप से कम किया गया है।

केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कुल आवंटन परिव्यय में 12% की कमी आई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मौजूदा संकट को बढ़ाता है। जबकि मनरेगा के लिए, चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों के लगभग 98,000 करोड़ रुपये आने के बावजूद, बजटीय आवंटन पिछले वर्ष की तरह ही 73,000 करोड़ रुपये पर रहा। इसमें से लगभग 18,350 करोड़ रुपये पिछले वर्षों से लंबित हैं। इसलिए अगले साल के लिए करीब 54,650 करोड़ रुपये ही उपलब्ध हैं।

यदि सरकार सभी सक्रिय जॉब कार्ड धारक परिवारों को काम की कानूनी गारंटी प्रदान करना चाहती है, जो कि 9.94 करोड़ है, तो वर्तमान बजटीय अनुमान को देखते हुए, वह प्रति व्यक्ति प्रति दिन की 334 औसत लागत² पर केवल कुछ 16 दिन प्रदान करने में सक्षम होगी।

² इस वर्ष से 12% वृद्धि को ध्यान रखते हुए प्रति व्यक्ति लागत की गणना की गई।

2015-16 से, वार्षिक बजट आवंटन कार्यक्रम के तहत रोजगार चाहने वाले सभी लोगों को काम प्रदान करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं रहा है। वास्तव में, हर साल बजट का लगभग 80-90% पहले 6 महीनों के भीतर समाप्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन पर काम की भारी मंदा आती है। अपर्याप्त बजट आवंटन के कारण सरकार सभी सक्रिय जॉब कार्ड धारक परिवारों को रोजगार नहीं दे पा रही है। यह सर्वविदित है कि नरेगा ने पिछले कुछ वर्षों में लाखों संकटग्रस्त परिवारों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य किया है और ग्रामीण भारत को वित्त वर्ष 2020-21 में एकतरफा राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण अभूतपूर्व बेरोजगारी से निपटने में मदद की है। इसने ग्रामीण भारत में बेरोजगारी के लिए लगभग एक टीके के रूप में काम किया है जो अभी भी जीवन और आजीविका के भारी नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने नरेगा के तहत काम करने वाले 7.5 करोड़ घरों के रिकॉर्ड में 11 करोड़ श्रमिकों के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, वित्त वर्ष 2021-22 में, बजट आवंटन में 34% की कमी के कारण ज़मीनी स्तर पर रोजगार सृजन बहुत कम हुआ। सरकार ने बाद में ग्रामीण भारत में काम की बढ़ती जरूरत को देखते हुए 25000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट जोड़ा। केंद्र से फंड जारी करने में काफी देरी के कारण कार्यान्वयन में लगातार रुकावटों के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6.74 करोड़ परिवारों के 9.75 करोड़ श्रमिकों ने नरेगा में काम किया है।

हमने अपने पूर्व बजट नोट में सिफारिश की है कि सभी सक्रिय जॉब कार्ड धारक परिवारों के लिए अधिकतम रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 3.62 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। सरकार ने एक बार फिर अपने उन लाखों ग्रामीण नागरिकों को विफल कर दिया है जो अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर निर्भर हैं।

हम, नरेगा संघर्ष मोर्चा के सदस्य, नरेगा के लिए इस हास्यास्पद रूप से कम बजट आवंटन पर अपनी गहरी निराशा व्यक्त करते हैं और हम आग्रह करते हैं कि केंद्र सरकार को कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने के लिए एक महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

हम देश भर में सोशल ऑडिट को मजबूत करने के लिए त्वरित कार्रवाई की भी उम्मीद करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों में स्वतंत्र सोशल ऑडिट नियमित हो जाएं, निष्कर्ष सार्वजनिक डोमेन में रखे जाएं और प्रत्येक अनियमितता के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अधिक जानकारी के लिए nrega.sangharsh.morcha@gmail.com पर लिखें या

Debmalya: 7294184845 | Anuradha: 9433002064 | Chakradhar: 9246522344 | Tapojay: 7718011678 | Mukesh: 9468862200 को नरेगा संघर्ष मोर्चाकी ओर सेसेसंपर्क करें।